

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में भारतीय रेल द्वारा रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। लेखापरीक्षा ने 2007 से 2013 तक की अवधि को कवर किया।

यह रिपोर्ट रेल मंत्रालय तथा जोनल रेलवे से सम्बंधित फाइलों तथा दस्तावेजों की सखीक्षा से तैयार की गई है। विशेष उद्देश्य वाहनों के साथ किए गए करार की भी जांच की गई।

रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।